

## आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 08.06.2024

समय : 0705

<><><><><><><><>

- श्री नरेन्द्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।
- ग्रेट निकोबार के ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के मसौदे पर जन-सुनवाई बाईस जून को होगी।
- रिजर्व बैंक ने भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने में डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के बारे में विभिन्न आयामों की जांच के लिए समिति का गठन किया।
- चिकित्सा अधीक्षक ने सभी निजी अस्पतालों और क्लीनिकों से अपने बायो मेडिकल अपशिष्टों को निपटान के लिए जी. बी. पंत. अस्पताल में भेजने की अपील की है।
- पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद जल शुल्क, संरक्षण शुल्क और सम्पत्ति कर की अदायगी के लिए क्यू. आर. कोड. की सुविधा शुरू करेगा।

<><><><><><><><>

कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी और उनके नए मंत्रिमण्डल को शपथ दिलाएंगी। इससे पहले, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में एन. डी.ए. के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा जिसमें

कहा गया कि नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया है। एनडीए के घटक दलों की ओर से समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा गया। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उन्होंने राष्ट्रपति को बताया है कि वे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने बताया कि मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और मौका दिया है और यह अट्ठारहवीं लोकसभा नई और युवा ऊर्जा का सदन है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिर सरकार देश और इसकी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ युवाओं के लिए हितकारी साबित होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।



ग्रेट निकोबार के ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए संबंधित कम्पनी द्वारा तेईस मई को सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट का मसौदा प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय, कैम्पबेल-बे के सहायक आयुक्त कार्यालय और शास्त्रीनगर तथा गांधीनगर, कैम्पबेल-बे के प्रधान कार्यालय में लोगों की समीक्षा के लिए उपलब्ध है। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में सभी संबंधित हितधारकों को अट्ठारह जून शाम पांच बजे तक विभाग को लिखित रूप में अपनी टिप्पणी या आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। टिप्पणियां मेल के ज़रिए भी भेजी जा सकती है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग इस संबंध में बाईस जून को दिन में ग्यारह बजे कैम्पबेल-बे के गांधी नगर सामुदायिक भवन और दोपहर

तीन बजे शास्त्री नगर में जन-सुनवाई करेगा। सभी संबंधित हितधारकों को जन-सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा गया है।

<><><><><><>

भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया – एन.पी.सी.आई. के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.पी. होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो डिजीटल भुगतान प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के विभिन्न आयामों की जांच करेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वर्तमान में डिजिटल भुगतान के विभिन्न माध्यम, बैंक, एन.पी.सी.आई., कार्ड नेटवर्क और भुगतान ऐप विभिन्न तरीकों की धोखाधड़ी से बचने के उपाय करती हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में नेटवर्क आधारित निगरानी और विभिन्न भुगतान माध्यमों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए वास्तविक समय आधारित डेटा साझा करना महत्वपूर्ण है।

<><><><><><>

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीए ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-नीट-यूजी की कट ऑफ में वृद्धि परीक्षा की प्रतिस्पर्धा और उम्मीदवारों के उच्च प्रदर्शन मानको को दर्शाती है। एजेंसी ने नीट यूजी परिणामों के संबंध में हाल के विवाद के संदर्भ में यह स्पष्टीकरण जारी किया। एजेंसी ने आगे कहा कि एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के पुराने और नए संस्करणों में अंतर के कारण, विषय विशेषज्ञों ने कहा कि एक विकल्प के स्थान पर दो विकल्पों को सही माना जाना चाहिए। छात्र-छात्राओं की चिंताओं की जांच के लिए गठित शिकायत निवारण समिति ने कहा कि परीक्षा के समय के नुकसान का पता लगाया गया था और ऐसे उम्मीदवारों को उत्तर देने की दक्षता और बर्बाद हुए समय के आधार पर अंकों के

साथ मुआवजा दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से समिति ने सुनिश्चित किया कि इन केंद्रों पर परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया।

<><><><><><>

चिकित्सा अधीक्षक ने सभी निजी अस्पतालों और क्लीनिकों से अपने बायो मेडिकल अपशिष्टों को निपटान के लिए जी बी पंत अस्पताल में भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जी बी पंत अस्पताल में निपटान के लिए भेजी जाने वाली अपशिष्टों को नवीनतम बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित रूप से अलग किया जाना चाहिए। अलग किए गए कचरे को उसकी सामग्री के अनुसार प्रमाणित किया जाना चाहिए। लाल, नीले और सफेद बैगों को निपटान के लिए नगरपालिका परिषद को भेजा जाता है। इसलिए इन बैगों की सामग्री को कीटाणुरहित कर सही तरीके से लेबल किया जाना चाहिए। सूखे और गीले कचरे को भी अलग-अलग भेजने की आवश्यकता है। ऐसा न करने पर जी बी पंत अस्पताल द्वारा कोई भी बायो मेडिकल अपशिष्ट प्राप्त नहीं किया जाएगा।

<><><><><><>

पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद जल शुल्क, संरक्षण शुल्क और सम्पत्ति कर की अदायगी के लिए क्यू आर कोड की सुविधा शुरू करेगा। परिषद के कर्मचारी सभी वार्डों में घर-घर जाकर बिलों का वितरण करेंगे। निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे निरंतर सेवा और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए चालू वित्त वर्ष के अपने बकाया और पिछले वर्षों के सभी शेष बचे हुए बिलों का तुरंत भुगतान करें। किसी भी विसंगतियों के लिए नगरपालिका परिषद के राजस्व अधिकारी या सहायक प्रबंधक, आई टी से संपर्क किया जा सकता है।



दक्षिण अंडमान शहरी परियोजना में आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार दस से तेरह जून के बीच विभिन्न चरणों में आर्टम पहाड़ स्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में लिया जाएगा।

उधर, अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी में अनुबंध के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। इक्कीस जून को एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक के कार्यालय में सुबह दस बजे से दस्तावेजों की जांच का कार्य किया जाएगा। दावे और आपत्तियां चौदह जून की शाम साढ़े चार बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।

इस बीच, स्कूल ऑफ नर्सिंग में तीन वर्षीय सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रम के लिए स्थानीय योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। कॉलेज प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पन्द्रह जून से पन्द्रह जुलाई के बीच आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों की अस्थायी सूची उन्नीस जुलाई को जारी होगी।



अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के नाम में परिवर्तन किया गया है। जिला प्रशासन की स्वीकृति के बाद अब इसे अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के नाम से जाना जाएगा।



